(ग) इस बारे में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

समाचार पत्र वित्त निगम

226. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री द० रा० परमार :
श्री वाल्मीकी चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री रा० वें० नायक :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री धी० ना० देव :
श्री कु० मा० कौशिक :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री भगवान दास :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब सरकार का विचार उन छोटे समाचारपत्रों के लिये समाचार पत्र वित्त निगम स्थापित करने का है जिनके पास संसाधनों की कमी है,

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). कुछ समय पूर्व प्रेस परिषद को भेजे गये एक पत्र के उत्तर में, मैंने यह सलाह दी थी कि समाचारपत्रों को आर्थिक कठिनाइयों में सहायता देने के लिये एक समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना की जाए जिसका एक स्वतन्त्र बोर्ड हो। इसके अनुसार परिषद को एक पत्र भेजा गया है कि वे इस मामले में मार्गदर्शन के लिये समाचार वित्त निगम की योजना के ब्यौरे, विशेष रूप से निदेशक बोर्ड की रचना उनके चयन के तरीके तथा संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन मोटे-मोटे सिद्धान्तों, जिनके आधार पर समाचारपत्रों को आर्थिक सहायता दी जानी है, के बारे में सलाह दें। परिषद ने यह बताया है कि वे फरवरी, 1969 के अन्त तक अपने विचार दे सकेंगे। परिषद के उत्तर आ जाने पर मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

पूर्वी अफ्रीका के देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

227. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प० मु० सईद :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के गत सत्र में पूर्वी अफ्रीका के देशों में रहने वाले भारतीयों का कोई प्रतिनिधि मंडल अथवा ब्रिटिश पारपत्र वाले भारतीयों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिला था;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को कोई ज्ञापन दिया था जिसमें वहां रहने वाले भारतीयों की कठिनाइयों का उल्लेख था और इन कठिनाइयों के समाधान करने के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये थे तथा उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां । कीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल डा० सांढू के नेतृत्व में नवम्बर '67 में भारत आया था और उसने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था ।

(ग) इस प्रतिनिधि मंडल ने यह सुझाव दिया था कि (i) कीनिया में रहने वाले ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतमूलक लोगों पर जो वीजा व्यवस्था लागू होती है वह खतम होनी चाहिए और (ii) जो लोग भारत ब्रिटिश करार के अन्तर्गत नहीं भी आते उन्हें भी स्थायी रूप से बसने के लिए भारत आने की इजाजत दी जानी चाहिए । विचार विनिमय के बाद यह प्रतिनिधि मंडल इस बात से संतुष्ट हो गया कि बीजा व्यवस्था जारी रहना आवश्यक है । बहरहाल, भारत सरकार ने इस प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वह भारत में फिर से बसने के लिए उन व्यक्तियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी जिन पर मौजूदा भारत ब्रिटिश करार लागू नहीं होता ।

इसरायली नागरिकों का भारत में आना

228. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इसरायली नागरिकों को भारत आने से निरुत्साहित करती है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले पांच वर्षों में कितने इसरायली अधिकारियों, नागरिकों तथा मंत्रियों ने भारत आने के लिए वीज़ा मांगे थे और कितने लोगों को वीज़ा दिये गये ;

(ग) क्या सरकार का विचार गुटों से अलग रहने की अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए इसरायली सरकार के विरुद्ध अरब लोगों को अपना सक्रिय समर्थन न देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अरब देशों द्वारा पाकिस्तान का खुले रूप में समर्थन किये जाने के बावजूद भी अरब लोगों का सक्रिय समर्थन करना भारत के हित में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):

(क) जी नहीं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) और (घ). भारत ने अरब को जो समर्थन दिया है, वह इस सुदृढ़ विश्वास पर आधारित है कि किसी भी आक्रमण से प्राप्त लाभ आक्रमणकारी के पास नहीं रहने चाहिए । यह गुट निरपेक्षता की नीति के